SHRI VASANT SATHE: I further demand that the entire correspondence exchanged between the Prime Minister and the ex-Home Minister be placed on the Table of the House. I hope Government will come out with a definite reply.

(ii) DELAY IN ANNOUNCING NATIONAL POLICY ON RESERVATION OF POSTS IN SERVICES FOR BACKWARD CLASSES.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष जी, बिहार सरकार द्वारा विधान सभा में यह घोषणा की गई थी कि प्रथम अप्रैल, 1978 से सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिये 26 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाएगा। इस मामले को लेकर बिहार में कुछ छुट-पुट घटनायें घटीं तब केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये बिहार सरकार से आग्रह किया और मामले को अपने अधीन ले लिया कि इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति तय की जाएगी। अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया जाना, काफी शंकाओं को पैदा करता है। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में 25 से 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया जाएगा, परन्तु अभी तक इस दिशा में किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है और जहां बिहार सरकार द्वारा, जो जनता पार्टी की प्रादेशिक सरकारों में प्रथम सरकार है, 26 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी गई, उसको केन्द्रीय सरकार के आदेश से स्थगित रखा गया है। इस के कारण समस्या उलझती जा रही है। अतः सरकार तुरन्त इस दिशा में फैसला करे।

(iii) DEMILITARISATION OF INDIAN OCEAN.

SHRI DHIRENDRA NATH BASU (Katwa): Sir, the Indian Ocean should be a zone of peace and India and all the littoral countries and all political parties have appealed to the U.N. for making it a zone of peace. It is regretted that two Big powers—USA and Russia—are not coming for demilitarization on Indian Ocean. It appears that the recently concluded special disarmament session of the U.N. at New York has received only casual attention at the session. The emphasis appeared to be mainly on the numerous dangers posed by nuclear weapons. India has again reminded the Big Powers, particularly the USA and Russia of their talks on the Indian Ocean more than a year ago when their leaders, President Carter and Mr. Brezhnev had both spoken in terms of littoral States are understood to have joined India in appealing to the two Powers to go back to their earlier goal of total demilitarization. While nations of the area have no objection to the Big Powers enjoying the freedom of the seas for free passage for their ships through the Ocean, they would not like them to establish their military presence in the Ocean as a permanent feature. I am requesting the hon. Minister to make a statement in this connection.

(iv) REPORTED POOR PERFORMANCE OF CALCUTTA STATION OF ALL INDIA RADIO.

SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): Sir, the people of West Bengal cannot listen properly the radio programmes broadcast by Calcutta Station due to poor transmission system. Practically due to its poor and unreliable performance, it is impossible for the people of North Bengal to tune Calcutta Centre of All India Radio faithfully. As a result, people from various districts of West Bengal unintentionally are forced to listen to the programmes of the neighbouring countries like Bangladesh etc., for

their better and reliable performance. This is undoubtedly a national failure of Information and Broadcasting Ministry of Government of India. On the other hand this forcible tuning in to foreign radios will definitely create a great perplexity among the law abiding citizens of India.

You can very easily tune to All India Radio Stations like Cuttack, Patna, etc., from Delhi. But noise-free reception of Calcutta Station from Delhi for a few minutes even in the night is practically a big problem. It cannot be a natural failure when science is advancing so rapidly. Moreover, the geographical and political location of Calcutta demands a very powerful mass media system to enlighten its people for better guidance. Thus, I strongly protest against the poor performance of Calcutta Station and request the hon'ble Minister in-charge to instal at Calcutta high power equipments with the latest technology so that the radio link can be established with remote corners of West Bengal and its people can be saved from listening to unwanted foreign Radio Stations and thus a great confusion among them can be eliminated.

(v) REPORTED INCREASE IN ACCIDENTS BECAUSE OF NEGLIGENCE OF DRIVERS OF BUSES IN DELHI.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय को आप की अनुमति से उठाना चाहता हूं :

यह सामान्य अनुभव की चीज है कि दिल्ली में आये दिन अनियंत्रित बस चालन के कारण भयंकर दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रात में ही लोक सभा के दो सदस्य श्री मोहन भैया और श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला (खंडवा) को विजय चौक के पास बस ने दबा दिया जो अभी बड़ी ही खतरनाक स्थिति में वैलिंगडन अस्पताल में हैं। एक तो बसों में अत्यधिक भीड़ रहती है, और अक्षम, वृद्ध, बीमार एवं बच्चे बिना खतरा मोल लिये चढ़ नहीं पाते, कितने ही चढ़ने के समय गिर कर घायल हो जाते हैं। लेकिन उससे भी अधिक दुर्घटना तब होती है जब बस चालक यात्रियों के उतरने उतरते ही बस चला देते हैं एवं यात्री गिर पड़ते हैं। इसके अलावा बस इस कदर भ चलाये जाते हैं कि आगे बगल आदि कुछ नहीं देखा जाता है। यदि आंकड़ा लिया जाए कि कितनी जगहें टक्कर लगती हैं, कितने लोग घायल होते हैं तो स्थिति प्रकट हो जाएगी। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव होंगे :

(1) दफ्तर के समय में बसों की संख्या अभी से चौथाई और बढ़ाई जाए।

(2) जब तक यात्री उतर न जायें कोई बस ड्राइवर बस आगे न बढ़ाए।

(3) इसकी जांच के लिए सरकार के ट्रैफिक अफसर रहें जो बसों के ठहराव में उसकी जांच कर तत्काल चालान करें एवं स्पीडो-मीटर लगा कर स्पीड चैक की जाये।

(4) बस चालकों को दुर्घटना से बचने के उपाय बताये जाय एवं हर छः माह पर एक सुरक्षा सप्ताह मनाया जाये।

(5) निर्दोष राहगीरों को राह की दुर्घटनाओं के लिये सरकार क्षतिपूर्ति करे एवं उसका खर्च उस वाहन के मालिक से वसूले।